VERDICTUM.IN

2026:AHC:84410

AFR

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

WRIT - A No. - 12905 of 2010

Jagdamba Prasad Pandey
.....Petitioner(s)

Versus

State of U.P. and Others
.....Respondent(s)

Counsel for Petitioner(s)	:	Diwakar Mishra, Raj Narayan Tiwari, Shyamdhar Pandey
Counsel for Respondent(s)	:	Ajit Kumar Singh, C.S.C., Mritunjay Mohan Sahai

Court No. - 32

ORAL ORDER

HON'BLE SAURABH SHYAM SHAMSHERY, J.

1. Heard Sri Shyamdhar Pandey, learned counsel for petitioner and Sri M.M. Sahai, learned counsel for respondent-Road Corporation.

2. The petitioner was a Conductor with respondent-Corporation. On 23.06.2004 when he was discharging duties as Conductor of Vehicle No. UP-42-T/1633 from Faizabad to Akbarpur, an inspection was conducted wherein it was found that he has not issued tickets to 59 passengers in bus though he has filled paybills.

3. In aforesaid circumstances, petitioner was served with a charge sheet and inquiry report dated 19.09.2004 was submitted. Subsequently, a second show cause notice was issued by Assistant Regional Manager, Akbarpur passed an order of punishment dated 15.02.2005 whereby petitioner was terminated from service. Subsequently, petitioner has filed a representation before Regional Manager, Faizabad and vide order dated 09.11.2006, punishment order was set aside and matter was remitted back for fresh consideration.

4. In aforesaid circumstances, inquiry was conducted afresh and vide inquiry report dated 04.03.2009, the charge was found proved in part. For

VERDICTUM.IN

reference, relevant part of order is quoted below :-

> "अधोहस्ताक्षरी द्वारा सम्पूर्ण प्रकरण पत्रावली का विधिवत अवलोकन किया गया। निरीक्षण के समय बस में कुल 59 यात्री यात्रा कर रहे थे जिसकी टिकट वाइज मार्ग पत्र पर परिचालक द्वारा प्रविष्टि कर दी गयी थी जिसे निरीक्षण कर्ता एवं आरोपी द्वारा स्वीकार किया गया है। आरोपी के पेट में दर्द होने के कारण टिकट पर कहां से कहां तक अंकित नहीं किया गया जबकि टिकट का यात्री सहित यात्रारत यात्रियों के पास उपलब्ध था यदि आरोपी की मनसा दूषित रहती तो उनको देय टिकटों का नम्बर वाइज अंकन मार्ग पत्र पर नहीं करता। आरोपी का दायित्व था कि यात्रियों को टिकट बनाकर उपलब्ध कराने के उपरांत मार्ग पत्र पर प्रविष्टि करने के बाद बस संचालित कराता लेकिन ऐसा न कर केवल यात्रियों की संख्या मार्ग पत्र पर करके बिना टिकट बनाये वाहन संचालित करा दिया गया जिसके लिए आरोपी दोषी प्रतीत होता है।
>
> अतः उक्त विवेचना एवं प्रकरण पत्रावली के आधार पर मै इस निष्कर्ष पर पहुचता हूँ कि श्री जगदम्बा प्रसाद पाण्डेय परिचालक (आरोपी) अकबरपुर डिपो जो वर्तमान में शाहगंज डिपो में कार्यरत है पर लगाया गया आरोप आंशिक रूप से सिद्ध पाया जाता है।"

5. The Disciplinary Authority thereafter issued a show cause notice along with a disagreement note, though admittedly, no specific reason was assigned therein and petitioner was asked to submit his reply within 15 days. The petitioner submitted a reply and asked respondents to provide reasons for disagreement. Accordingly, second notice was issued on 07.08.2009 was issued wherein concerned respondent provided reasons for disagreement. Relevant part thereof is quoted below :-

> "2- आपके उक्त प्रार्थना पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि रिपोर्ट कर्ता की मृत्यु हो जाने के कारण प्रकरण के द्वितीय जांच में उनकी बयान नहीं लिया गया है। आपने अपने आरोप पत्र के उत्तर में निरीक्षण स्थल की दूरी डेढ से 02 किमी० बताया गया है, जबकि पूर्व में हुई जांच में जांच अधिकारी, द्वारा प्रतिपरीक्षण के समय रिपोर्टकर्ता से पूछे गये प्रश्न के उत्तर में अकबरपुर से निरीक्षण स्थल की दूरी 12 किमी० बताया गया है, जिसमें विरोधाभास है। प्रकरण में अभिलेखनीय आधार पर जांच आख्या तैयार की गयी है। अतः आपको अन्तिम रूप से सूचित किया जाता है, कि कारण बताओं नोटिस का उत्तर 03 दिन के अन्दर प्रेषित करें, अन्यथा प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही कर दी जायेगी।"

6. Admittedly, petitioner has not submitted any reply within prescribed period and he submitted a belated reply on 01.09.2009 whereas on same day, impugned order was passed, whereby a major punishment of termination from service was passed. Relevant part of said order is mentioned hereinafter :-

VERDICTUM.IN

"मेरे द्वारा रिपोर्टकर्ता की रिपोर्ट, जाँच आख्या प्रति परीक्षण के समय आये तथ्यों का सम्यक अवलोकन किया गया, और पाया कि आरोपी द्वारा अपने आरोप पत्र के उत्तर में लिखा है कि यात्रियों से पूछ कर उनकी संख्यानुसार मार्ग पत्र पर प्रविष्टि अकबरपुर से बसखारी कर दी गयी थी। वही रिपोर्टकर्ता ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि वाहन का भौतिक निरीक्षण किया जा रहा था, तभी आरोपी द्वारा यात्रियों को भड़का दिया गया। जिससे यात्री हंगामा करने लगे। जिसके कारण आरोपी से टिकट तुरन्त नहीं लिया जा सका, और स्थिति को देखते हुये आरोपी के कथनानुसार टिकटो की प्रविष्टि भी मार्ग पत्र पर आरोपी से ही करवानी पड़ी, और यात्रियों के दवाब के कारण मार्ग पत्र के अनुसार उसकी क्लोजिंग भी निरीक्षण कर्ता द्वारा करनी पड़ी। आरोपी द्वारा कारण बताओ नोटिस के उत्तर के साथ सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र अतरौलिया आजमगढ़ की दवा की पर्ची संलग्न की है, जो दिनांक 22.06.04 की है। साथ ही जब आरोपी के पेट में दर्द था तो दिनांक 23.05.04 को फैजाबाद से बुदनपुर जाते समय डिपो पर तैनात उपधिकारियों/अधिकारियों को बताना चाहिये था, परन्तु आरोपी द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया। प्रकरण की द्वितीय जांच में आरोपी ने निरीक्षण स्थल की दूरी डेढ से 02 कि०मी० बताया है। जब कि पूर्व में हुई जांच अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण के दौरान रिपोर्ट कर्ता से पूछे गये। प्रश्न के उत्तर में अकबरपुर से निरीक्षण स्थल की दूरी 12 कि०मी० बताया गया है। जैसा कि पत्रावली में रिपोर्टकर्ता द्वारा बताया गया है कि निरीक्षण स्थल से अकबरपुर की दूरी 12 कि०मी० है। इसी बीच कुड़की नामक पेपर स्टापेज है। जो अकबरपुर से 08 कि०मी० की दूरी पर है। आरोपी का उत्तर दायित्व था कि बस में बैठे यात्रियों को नगर सीमा के अन्दर ही टिकट बनाकर और मार्ग पत्र पर प्रविष्ट करके ही वाहन को आगे बढाता परन्तु उनके द्वारा 12 कि०मी० की दूरी तक एक भी टिकट नहीं बनाया गया। बस स्टेशन से एक पेपर स्टापेज पार करके 12 कि०मी० की दूरी निरीक्षण स्थल से टिकट बनाने का कोई औचित्य नहीं है। जैसा कि आरोपी ने यह भी स्वीकार किया है कि निरीक्षण स्थल तक कोई भी टिकट नहीं बनाया गया था। इस प्रकार परिचालक भ्रष्टाचार में संलिप्त हो करके विभागीय नियमों एवं निर्देशों के विरूद्ध है। जिसके कारण आरोपी दोषी है। आरोपी द्वारा द्वितीय जाँच में कारण बताओं नोटिस का उत्तर भी प्रस्तुत नहीं किया है। आरोपी द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर न देना स्पष्ट करता है कि कारण बताओ नोटिस में दिया गया दण्ड उसे स्वीकार है। मेरे अभिमत में प्रस्तावित दण्ड के अनुसार दण्डादेश पारित किया जाना उचित है।

अतः श्री जगदम्बा प्रसाद पाण्डेय, परिचालक अकबरपुर डिपों वर्तमान शाहगंज डिपो को कारण बताओ नोटिस में प्रस्तावित दण्ड को पारित करते हुये निलम्बन काल का अवशेष वेतन जब्त करते हुये सेवा से प्रथक किया जाता है।"

7. The petitioner thereafter approached this Court by filing a Writ Petition No. 58141/2009 which was disposed of vide order dated 10.11.2009 with liberty to file an appeal being alternative remedy.

8. Accordingly, petitioner filed an appeal before Regional Manager,

VERDICTUM.IN

UPSRTC, Azamgarh Region, Azamgarh which was dismissed vide order dated 03.02.2010 and relevant part of it is mentioned below :-

> "प्रकरण पत्रावली प्राप्त होने पर मेरे द्वारा प्रकरण से संबंधित रिपोर्ट जारी आरोप पत्र आरोप पत्र के उत्तर जांच अधिकारी की जांच आख्या जारी कारण बताओं नोटिस, प्रत्यावेदन एवं प्राप्त आख्या सहित सम्पूर्ण प्रकरण पत्रावली का गम्भीरता पूर्वक गहन अध्ययन किया गया। और पाया कि चेकिंग के समय जिन टिकटों की प्रविष्टि प्रत्यावेदन श्री पाण्डेय द्वारा मार्ग पत्र पर की गयी उनमें जो टिकट निरीक्षण के द्वारा रोके गये, सभी खाली (ब्लैंक) थे। और निरीक्षण स्थल तक उक्त टिकटों के यात्री वास्तव में बिना टिकट ही थे और प्रकरण से अपने आपको बचाने हेतु यात्रियों को बहकाना भी इसी तारतम्य मे स्पष्ट समझ में आता है। अतः मेरे अनुसार प्रत्यावेदन को दिया गया दण्ड उचित है।
>
> अतः श्री जगदम्बा प्रसाद पाण्डेय भूतपूर्व परिचालक शाहगंज डिपो द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन बलहीन पाये जाने के कारण निरस्त (रिजेक्ट) किया जाता है।"

9. Aforesaid orders dated 01.09.2009 and 03.02.2010 are under challenge in this writ petition.

10. Learned counsel for petitioner has argued vehemently and referred orders passed by respondents annexed in writ petition to the effect that on date of inspection, the petitioner was suffering with stomach pain and inspection was conducted within two kilometers from starting point of bus, therefore, he was not able to distribute tickets though after making count of passengers, he has filled pay-bills and has received the ticket money also, therefore, there was no loss of Corporation. Since author of inspection report was meanwhile expired, therefore, report was not proved during subsequent inquiry. None of passengers has given any statement and punishment was shockingly disproportionate.

11. Per contra, learned counsel for respondent-Corporation has supported impugned order and submitted that it was a case where disciplinary authority has made a disagreement to inquiry report submitted in second round of disciplinary proceedings and has made a specific reason in second notice, however, petitioner has not submitted any reply within stipulated time, therefore, on basis of material available, it was found that petitioner has committed misconduct that admittedly he was carrying 59 passengers without ticket and without any reasonable explanation with specific finding that inspection was conducted after about 12 kilometers

VERDICTUM.IN

from starting point of bus and not after 2 kilometers as alleged by petitioner. Therefore, there was no explanation for not providing tickets even after such a long journey.

12. I have considered above submissions and perused the records.

13. The Supreme Court in **MD, North-East Karnataka Road Transport Corpn. v. K. Murti, (2006) 12 SCC 570** has held that carrying passengers without ticket is a serious misconduct which could invite major punishment of termination. Relevant paragraph of said judgment is quoted below :-

> "8. The learned counsel for the appellant, at the time of hearing, placed strong reliance on the two decisions of this Court, one in Regional Manager, Rajasthan SRTC v. Ghanshyam Sharma [(2002) 10 SCC 330 : 2003 SCC (L&S) 714] which was also a case of bus conductor carrying passengers without issuing tickets. This Court, in the above case, held that carrying the passengers without tickets amounts to dishonesty or grave negligence and for such misconduct punishment of removal from service is justified. This Court also further observed that the Labour Court was not justified in directing the reinstatement with continuity of service but without back wages. **This Court has also relied upon a judgment in Karnataka SRTC v. B.S. Hullikatti [(2001) 2 SCC 574 : 2001 SCC (L&S) 469] . In the said judgment, this Court has held that in such cases where the bus conductors carry passengers without ticket or issue tickets at a rate less than the proper rate, the said acts would inter alia amount to either being a case of dishonesty or of gross negligence and such conductors were not fit to be retained in service because such inaction or action on the part of**

VERDICTUM.IN

> **<u>the conductors results in financial loss to the Road Transport Corporation. This Court has also observed that in cases like the present, orders of dismissal should not be set aside</u>**. The learned counsel for the appellant also cited Divisional Controller, N.E.K.R.T.C. v. H. Amaresh [(2006) 6 SCC 187 : 2006 SCC (L&S) 1290] . In this case, this Court was considering the case of misappropriation of a small amount of State Road Transport Corporation's fund by a conductor and held it a grave act of misconduct, which resulted in financial loss to the Corporation. This Court also held that punishment of dismissal from service awarded by the disciplinary authority did not call for any interference by the Labour Court or the High Court and hence the order of reinstatement passed by the High Court was set aside. **<u>This Court also in a catena of decisions held that the Tribunal should not sit in appeal over the decision of any employer unless there exists a statutory provision in this behalf. This Court also observed that the High Court gets jurisdiction to interfere with the punishment in the exercise of its jurisdiction under Article 226 of the Constitution only when it finds that the punishment imposed is shockingly disproportionate to the charges proved</u>**."

14. In the first round of proceedings, a representation of petitioner was considered by the higher authority and a fresh inquiry report was sought. Accordingly, a fresh inquiry report was submitted and charge was found proved in part, however, Disciplinary Authority has made a disagreement on a factual aspect that petitioner has sufficient time to distribute tickets as bus was checked after about 12 kilometers from starting point, he filled pay-bills without issuing tickets.

15. The petitioner is not able to deny aforesaid either in disciplinary

VERDICTUM.IN

proceedings or before this Court. The petitioner is also not able to deny that in normal circumstances, tickets are issued at first instance and pay-bills are filled subsequently and not vice versa. During inquiry, due process was followed. The petitioner was granted sufficient time to submit reply of notice of disagreement, however, he failed to do so.

16. The Appellate Authority has also rejected the appeal by a reasoned order. It is well settled that in cases of disciplinary proceedings, this Court cannot sit as Appellate Court to consider whether evidence was sufficient or not except in a case when findings are perverse which is not a case in hand. Carrying passengers without ticket is a serious misconduct and in this regard, Court takes note of above referred judgments and since petitioner has failed to provide any reasonable explanation that under which circumstances, without issue tickets to passengers, he could fill pay-bills in advance, therefore, this Court does not find any reason to interfere with impugned order in limited writ jurisdiction and for that Court takes note of a judgment of Supreme Court in **Bhupinderpal Singh Gill vs. State of Punjab and others, 2025 SCC Online SC 113**.

17. Accordingly, writ petition has no force, hence, **dismissed**.

(Saurabh Shyam Shamshery,J.)

April 16, 2026
N. Sinha